

यह निरीक्षण प्रतिवेदन प्रभारी च कत्सा धकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कालसी देहरादून द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय प्रभारी च कत्सा धकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कालसी देहरादून के माह 04/2012 से 01/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री पुष्पेंद्र चतुर्वेदी, लेखापरीक्षक, श्री देवेन्द्र कुमार दिवाकर सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 19.02/2018 से 22.02/2018 तक श्री डी. के. पपलानी वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के आंशिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-1

1. परिचयात्मक: इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है

(ii) (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: कालसी के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण आंचल में च कत्सा सुवधाए उपलब्ध कराना।

(iii) (अ) वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:

(धनराश लाख में)

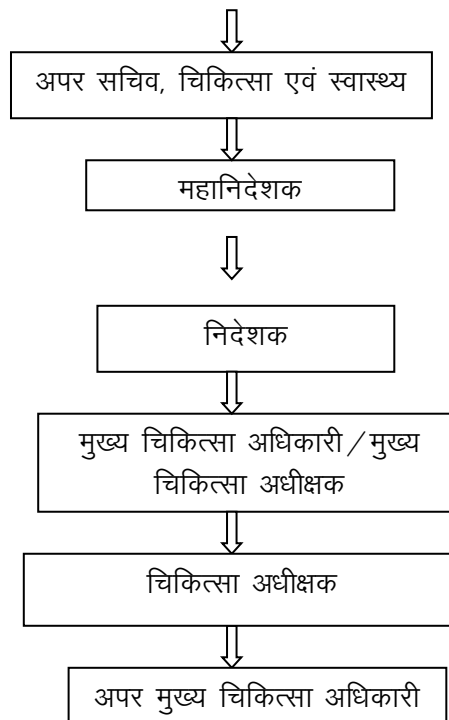
वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2012-13	शून्य	शून्य	150.86	134.15	213.46	206.17	-	23.99
2013-14	शून्य	शून्य	173.13	145.47	287.20	261.20	-	53.91
2014-15	शून्य	शून्य	126.80	114.91	296.32	291.95	-	17.38
2015-16	शून्य	शून्य	101.28	91.50	378.41	312.31	-	75.88
2016-17	शून्य	शून्य	91.32	71.06	413.94	344.46	-	89.74
2017-18 (01/2018)	शून्य	शून्य	--	--	464.60	392.58	-	-

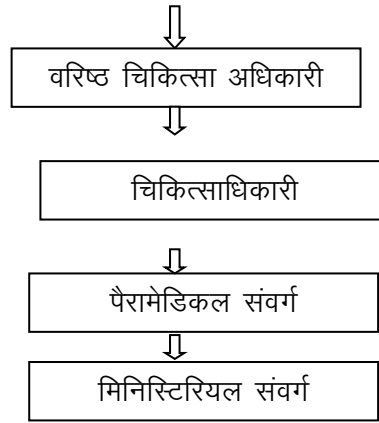
(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय ववरण निम्नवत है:

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय अधक्य (+)	बजट C.M.O. को वापस
2012-13	RCH Flexipool	3.76	24.35	22.97	0.45

	NHM Additionalaties	0.10	30.10	29.59	0.07
	Routine immunization	0.01	10.10	8.19	0
2013-14	RCH Flexipool	4.69	34.06	37.38	0
	NHM Additionalaties	0.54	9.45	8.31	0
	Routine immunization	1.92	7.87	9.13	0
2014-15	RCH Flexipool	2.42	62.05	61.07	0
	NHM Additionalaties	1.68	22.14	18.76	3.33
	Routine immunization	0.66	8.91	8.52	0
2015-16	RCH Flexipool	3.40	56.18	52.55	1.38
	NHM Additionalaties	1.73	26.74	22.61	2.46
	Routine immunization	1.05	8.85	9.02	0
2016-17	RCH Flexipool	5.66	52.12	49.07	3.20
	NHM Additionalaties	3.40	44.89	23.57	2.69
	Routine immunization	0.87	6.52	5.51	1.57
2017-18	RCH Flexipool	5.50	17.68	13.35	5.86
	NHM Additionalaties	22.04	22.42	39.79	0.72
	Routine immunization	0.32	4.46	4.04	0

(iv) इकाई को बजट आवंटन केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई श्रेणी C की है। वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:





- (v) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कालसी देहारादून को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी कये जा रहे हैं। यह निरीक्षण प्रतिवेदन प्रभारी चिकित्सा अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कालसी देहारादून की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 08/2017, 08/2016 एवं 08/2013 को वस्तुतः जांच हेतु चयनित किया गया।
- (vi) लेखापरीक्षा भारत के संवधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-2 'ब'

प्रस्तर 1: जननी सुरक्षा योजना योजना के अंतर्गत रु 19.15 लाख के अनिय मत व्यय

राष्ट्रीय कार्यक्रम जननी सुरक्षा योजना अप्रैल 2005 में प्रारम्भ की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव के लिए प्रोत्साहित करना था ताक मातृ एवं शशु मृत्यु की दर को कम किया जा सके जननी सुरक्षा योजना की निर्देशिका के अनुसार सरकारी अस्पतालों में संस्थागत प्रसव कराने पर महिलाओं को प्रोत्साहन राश के रूप में ग्रामीण क्षेत्र में रु 1400 एवं शहरी क्षेत्र में रु 1000 का भुगतान चैक के माध्यम से किया जाना चाहिए। योजना के अधीन प्रोत्साहन निधि के वितरण हेतु निर्धारित शर्तों के अनुसार (i) प्रसव की संभावित तिथि से 16 से 20 सप्ताह पूर्व प्रत्येक महिला लाभार्थी हेतु जे.एस.वाई. कार्ड भरा जाना चाहिए एवं सभी वांछित दस्तावेजों सहित उसे प्रसव की संभावित तिथि से 2 सप्ताह पूर्व संबन्धित स्वास्थ्य केंद्र के अधिकृत चिकित्सा अधिकारी के पास सत्यापन हेतु प्रस्तुत किया जाना चाहिए ताक लाभार्थी को डिसचार्ज करते समय प्रोत्साहन राश प्रदान की जा सके (ii) लाभार्थी को प्रसव के पश्चात कम से कम 48 घंटे स्वास्थ्य केंद्र में रुकना आवश्यक है, (iii) लाभार्थी को चिकित्सालय से डिसचार्ज करते समय अनिवार्य रूप से देय राश का भुगतान किया जाना चाहिए एवं (iv) प्रसव के सात दिन पूर्व या सात दिन पश्चात किया गया कोई भी भुगतान अवैध माना जाएगा। इसके अतिरिक्त आशाओं को नगद प्रोत्साहन राश दो कशतों में दी जाएगी, जिसमें प्रथम 50 प्रतिशत राश लाभार्थी महिला के स्वास्थ्य केंद्र से डिसचार्ज के पश्चात दी जाएगी वशर्त संबन्धित आशा गर्भवती महिला के साथ स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव के समय रही हो तथा अवशेष 50 प्रतिशत राश प्रसव के एक माह के पश्चात दी जाएगी जब बी.सी.जी. वैक्सीन बच्चे को दी गयी हो और नवजात शशुओं के जन्म के समय आशा ने देखभाल और जन्म के पंजीकरण में सहायता की हो।

कार्यालय प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, कालसी के जननी सुरक्षा योजना से संबन्धित लेखा अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि केंद्र में वर्ष 2012-13 से 01/2018 तक कुल 807 संस्थागत प्रसव हुये, जिनको ग्रामीण क्षेत्र हेतु निर्धारित रु 1400 एवं शहरी क्षेत्र हेतु निर्धारित रु 1000 की दर से 807 लाभार्थियों को 11.19 लाख का भुगतान किया गया। तथा आशाओं को रु 7.96 लाख का भुगतान किया गया। भुगतान का ववरण संलग्न है

अभिलेखों की जांच में पाया गया कि 04/2015 से 01/2018 तक की अवधि में जननी सुरक्षा के प्रत्येक मामले में JSY कार्ड प्रसव के समय या प्रसव के बाद भरे गए थे, जबकि दिशा निर्देशों के

अनुसार JSY कार्ड प्रसव की संभावित तिथि से 16-20 सप्ताह पूर्व भरा जाना चाहिए एवं प्रसव के बाद चिकित्साधिकारी को भुगतान के इस बात का प्रमाण पत्र देना चाहिए था कि लाभार्थी JSY के मानदंडों के अनुसार लाभ प्राप्त करने के पात्र है। लाभार्थी को प्रसव के पश्चात कम से कम 48 घंटे स्वास्थ्य केंद्र में रुकना आवश्यक है, परंतु 807 लाभार्थी में से मात्र एक लाभार्थी ही 48 घण्टे तक केंद्र पर रुकी। एवं 1257 आशाओं की रु 7.54 लाख का भुगतान एक ही कश्त में किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगत किए जाने पर प्रभारी चिकित्साधिकारी ने आपत्त स्वीकार करते हुये अवगत कराया कि JSY कार्ड प्रसव के समय ही भरे गये, लाभार्थी के आग्रह के बाद ही उन्हें डिस्चार्ज किया जाता है एवं जिला स्तर से निर्देश प्राप्त होने के बाद आशाओं को एक कश्त में भुगतान किया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि किसी भी स्तर पर दिशा निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया।

अतः जननी सुरक्षा योजना योजना के अंतर्गत रु 18.73 लाख के अनियमित व्यय का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

वर्ष	क्षेत्र	कुल संस्थागत प्रसवों की संख्या	48 घंटे रुकने वाले लाभार्थियों की संख्या	48 घंटे से कम रुकने वाले लाभार्थियों की संख्या	भुगतान किए गए लाभार्थियों की संख्या	देय धनराश	आशाओ की संख्या (एक ही कश्त में देय राश)	आशाओ को भुगतान
2012—13	ग्रामीण	101	0	101	101	132400	0	0
2013-14	ग्रामीण	75	0	75	75	103500	177	106200
2014-15	ग्रामीण	287	0	287	287	401300	367	220200
2015-16	ग्रामीण	193	0	193	193	270200	293	175800
2016-17	ग्रामीण	89	1	88	89	124600	292	175200
2017-18 (01/2018 तक)	ग्रामीण	62	0	62	62	86800	128	76800
कुल		807	1	806	807	1118800	1257	754200

भाग-2 'ब'

प्रस्तर-2- च कत्सकों को वाहन भत्ते के रूप में रु 1.24 लाख का अनियमन भुगतान।

उत्तर प्रदेश सरकार के पत्रांक संख्या महा0 निदे0(सी)या0 भ0/2002/2224 लखनऊ, दिनांक 06 सितंबर, 2000 के अनुसार पीएमएचएस एवं दंत च कत्सक सेवा वर्ग के च कत्सा धकारियों को कतिपय शर्तों एवं प्रतिबंधों के साथ शासनादेश संख्या सा-4-229.दस 2000-626-2000 दिनांक 10 मार्च 2000 द्वारा वाहन भत्ता भी पुनरीक्षित की गयी थी।

इस संबंध में यह भी आदेशित किया गया था कि वाहन भत्ता च कत्सकों को उनके सामान्य कार्य के घंटों के अतिरिक्त माह में कम से कम 25 वजिट पर ही अनुमान्य होगा एवं इसके लिए वजिट रजिस्टर रखना होगा। महीने के अंत में प्रत्येक च कत्सक अपने पास रखे वजिट रजिस्टर को अपने अगले उच्चाधिकारी को दिखाकर यह प्रमाण पत्र दे कि उसने महीने में आवश्यक 25 अतिरिक्त वजिट पूरी कर ली है। उक्त निर्देशों को कड़ाई से पालन करने हेतु भी निर्देशित किया गया था।

साथ ही उत्तराखण्ड शासन के वक्त (वे0 अ0- सा0 नि0) अनु0-7 संख्या-700/XXVII(7)30(5)/2013 दिनांक 16 सितंबर 2013 के अनुसार सरकारी कार्य में की जाने वाली यात्राओं में उपयोग करने हेतु वतीय नियमों वाहन भत्ता पुनरीक्षित किया गया था जिसके अनुसार मोटर कार (जहां औसत स्थानीय यात्रा प्रतिमाह 400 Km से अधिक हो) को रु 1000/- से पुनरीक्षित कर रु 2700/- कर दिया गया था।

कार्यालय के लेखा अभिलेखों में जांच में यह पाया गया कि 02 च कत्सकों द्वारा वर्ष 2014-15 से 2017-18 तक रु 1.24 लाख (संलग्न ववरण के अनुसार) का वाहन भत्ता दिया गया था जब कि कसी भी च कत्सक द्वारा वजिट रजिस्टर नहीं बनाया गया था और नहीं इस प्रकार का कोई प्रमाण पत्र उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था जिससे यह प्रमाणित किया जा सके कि उनके द्वारा अतिरिक्त 25 वजिट पूरी कर ली हो बावजूद इसके उनको वाहन भत्ता अनुमन्य दिया जा रहा था जो लेखा परीक्षा तिथि तक जारी था तथा अनियमन था।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगत किए जाने पर प्रभारी च कत्सा धकारी द्वारा आपत्त स्वीकार करते हुये अवगत कराया गया कि भ्रमण कार्यक्रम इमरजेंसी पंजिका के द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है एवं वजिट पंजिका बना दी जाएगी। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि बिना वजिटिंग प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए, वाहन भत्ता अनुमन्य किया गया था।

अतः च कत्सकों को वाहन भत्ते के रूप में रु 1.24 लाख का अनियमन भुगतान का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरोँ का ववरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है			

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

---शून्य---

भाग-Vआभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु प्रभारी च कत्सा अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कालसी देहरादून तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न लिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं कये गये:

(i) जी.पी.एफ. लेजर

2. सतत् अनियमितताएं:

(i)

3. लेखापरीक्षा अवध में निम्न लिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं०	नाम	पदनाम
(i) 1	डा. नीरज राय	प्रभारी च कत्सा अधिकारी
(ii) 2	डा. वक्रम सिंह	प्रभारी च कत्सा अधिकारी
(iii) 3	डा. प्रदीप उनियाल	प्रभारी च कत्सा अधिकारी
(iv) 4	डा. राजीव कुमार दीक्षित	प्रभारी च कत्सा अधिकारी

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति प्रभारी च कत्सा अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कालसी देहरादून को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार सामाजिक क्षेत्र को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सामाजिक क्षेत्र